applied for withdrawals of initial deposit amount;

(b) the number of such applicants who have claimed refund from Lohia Machines Limited, Kanpur, till 31st October, 1985;

(c) how much of the dues have already been refunded;

(d) details of expected yearly production figures for the next five years and the allocation made available for sale, yearly at each selling centre (name of the dealers city1wise; and

(e) the reasons for not increasing the production of Scooters?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) 4,03,082.

(c) About Rs. 20 crores.

(d) Estimated production for the 5 years is:

1985	72,000
1986	1,00,000
1987	1,25,000
1988	1,25,000
1989	1,25,000

In addition, Vespa Car Co. Ltd. promoted jointly by Lohia Machines Ltd. and Piaggio & C.S.P.A. of Italy and licensed to manufacture 200,000 two-wheelers per annum, will also supply scooters against the bookings of Lohia Machines Ltd. The company afforts vehicles to dealers every quarter broadly in proportion to respective bookings.

(e) The Company is stepping up scooter production as per the scheduled programme.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2735. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1983–84 में देश के 92 तथा 1984–85 में 84 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को घाटा हुआ जो क्रमश: 1534.31 तथा 1305.18 करोड़ रुपये था ; और

(ख) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति ने इनको घाटे से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) लोक उद्यम सर्वेक्षण 1983–84 के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 92 उद्यमों ने कुल मिलाकर 1534.37 करोड़ रुपये का निवल घाटा उठाया है । 1984–85 के अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । किन्तु, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के 1984–85 के उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 84 उद्यमों ने कुल मिलाकर 1305.15 करोड़ रुपये का घाटा उठाया है ।

(ख) प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में कोई यथा निर्दिष्ट समिति नहीं गठित की गई है । किन्तु डा० अर्जुन सेन गुप्त की अध्यक्षता मे "सरकारी उद्यमो के सम्बन्धी नीति की समीक्षा करने के लिये समिति" गठित की गई थी तथा सरकार इस समिति की सिफारिशों की फिलहाल जांच कर रही है ।

2736. [*Transferred to the 19th December*, 1985.]

भारी उद्योगों से जुड़े आनुषंगिक उद्योग

2737. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में जापान जैसी कोई योजना नहीं है जिसके अनुसार प्रत्येक बड़े उद्योग के साथ जुड़े आनुषंगिक उद्योगो का जाल होता है तथा वहां गांवों को भी इसकी परिधि में ले लिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार अब भी देश का सबसे निर्धन राज्य है जबकि यहां सभी प्रकार के

संसाधनों का बाहुल्य है तथा वहां केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र में भारी उद्योगों में तीन करोड़ रुपये से भी अधिक लगे हुए हैं तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में उससे भी अधिक धनराशि लगी हुई है क्योंकि उस राज्य में कोई आनुषंगिक उद्योग नहीं है और न ही वहां छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग हैं ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में आनुषंगिक उद्योग स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) औद्योगिक विकास के लिए सरकार की नीति और कार्यक्रमों में अनुषंगीकरण को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में विशेष बल दिया गया है और देश भर में अनुषंगी उद्योगों का जाल फैलाने के लिए कुछ नीति विषयक उपाय किए गए हैं। सरकारी उद्यम ब्यूरों ने देश में अनुषंगी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार के सभी प्रतिष्ठानों को व्यापक मार्गदर्शीसिद्धान्त जारी किये हैं।

(ख) बिहार में, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 9 प्रतिष्ठानों ने अपनी आवश्यकता का माल खरीदकर अनुषंगी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी उद्यम ब्यूरों द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कार्रवाई पहले से ही शुरू कर दी है। इन नौ एककों को हिस्से-पुर्जों और उपकरणों का संभरण करने वाले लघु और अनुषंगी उद्योगों की संख्या वर्ष 1982–83 में 471 थी। जो वर्ष 1983–84 में 728 हो गई। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि बिहार में सरकारी क्षेत्र के एकक लघु और अनुषंगी उद्योगों को समर्थन देते रहे हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र में टेल्को और टिस्को जैसे एककों द्वारा लघु उप-संविदाकारों से माल व सेवाएं खरीदी जाने की सूचना मिली है।

(ग) सरकार ने अनुषंगीकरण कार्यक्रम को तीव्र बनाने के लिए हाल ही में कुछ और कदम उठाए हैं। बड़े एककों की स्थापना करने के लिए आशय पत्र स्वीकृत करते समय एक शर्त यह भी लगी होगी कि सरकार की आशानुरूप अनुषंगीकरण कार्यक्रम के क्षेत्रों के लिए गुंजाइश का भी पता लगाया जाएगा।

Inability to check fly ash and smoke pollution

2738. SHRI RAMCHANDRA BHARADWAJ:
DR. H. P. SHARMA:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the American firm, M|s. Air Correction International has been unable to check the fly ash and smoke pollution from the three units of the Indraprashtha Thermal Power Station of the Delhi Electric Supply Undertaking;

(b) if so, what was the cost of the equipment supplied by the U.S. firm for pollution control purposes at the Indraprastha station;

(c) what are the terms of the agreement with the said firm; and

(d) what action has taken in this regard to effectively control the pollution?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) Yes, Sir. The equipment supplied by M|s. Air Correction International has not squcceded in bringing down the dust emission from the three units of Indraprastha Thermal Power Station to the desired level as per contract.

(b) The cost of equipment supplied by the firm including the erection services is US dollar 2.1 million FAS New York and Rs. 56 lacs for indigenous components and erection services.

(c) As per the contract, the firm was supposed to provide collection efficiency of 99.78 per cent subject to equipment running on certain pre-designed paramteres.

(d) New Additional electro-static precipitators are proposed to be installed under the Centrally sponsored renovation and modernisation scheme.